International Journal of Research in Social Sciences And Humanities http://www.ijrssh.com
(IJRSSH) 2013, Vol. No. 3, Issue No. III, July-Sept ISSN: 2249-4642

भारत–अमेरिका सम्बन्ध

* डॉ. औमप्रकाश पंवार

** उपासना

* भूतपूर्व प्राचार्य, आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ब्राह्मणवास (जुलाना, जींद)
**पीएच.डी स्कोलर, राजनीति विज्ञान विभाग, मोनाड़ यूनिवर्सिटी, हापुड़ (यू.पी.)

भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। इन दोनों के पारस्परिक संबंध सदैव उतार–चढ़ाव के रहे हैं। अपने–अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थिति रखते हैं; लेकिन सामरिक व शक्ति के संदर्भ में दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति रखते है।[1] भारत–अमेरिका संबंधों का अध्ययन एक रोचक विषय है। ये सम्बन्ध सदैव पेचीदगियों में लिप्त रहे हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति पर जहाँ उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर में राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता का विभेद समाप्त होता जा रहा है तथा दोनों प्रक्रियाएँ आपस में एक दूसरे को काफी हद तक प्रभावित करने लगी हैं। अतः ऐसे बदलावों के बाद दोनों देशों के संबंधों का आकलन जरूरी हो गया है। विश्व परिदृश्य में आएं मूलभूत बदलावों ने भारत–अमेरिका संबंधों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है।

सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद भारत के लिए आवश्यक हो गया कि वह अमेरिका से मित्रता करे। भारत द्वारा आणविक अप्रसार सन्धि 1968 पर हस्ताक्षर न करने से दोनों देश के मध्य सम्बन्धों में दरार पड़ने लगी। 1994 में दोनों देशों ने थोड़ा सकारात्मक रूख अपनाते हुए हिन्द महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया तो अमेरिका बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि भारत के रूप में उसे विशाल बाजार मिल गया। जब 11 व 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका नाराज हो गया और भारत

IJRSSH

की कटु आलोचना की, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका विश्व में शक्ति संतुलन तथा अपना वर्चस्व कॉयम रखने के लिए दक्षिण एशिया में 21वीं सदी की उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत से मधुर व सहयोगात्मक संबंध स्थापित कर रहा है। इस शोध लेख द्वारा यही जानने का प्रयास किया गया है कि पोखरण द्वितीय के भारत अमेरिका संबंधों में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। एशिया में चीन की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए भी अमेरिका भारत से बेहतर संबंध बनाने को प्रयासरत है। अतः वर्तमान समय में भारत–अमेरिका सम्बन्ध किस दिशा में किस गति से बढ़ रहे हैं यह जानना भी इस शोध लेख का उद्देश्य है।

स्वातंत्र्योत्तर तथा स्वतंत्रता के पश्चात् भारत–अमेरिकी संबंधों पर यदि दृष्टिपात करें तो अगस्त 1947 तक यानी भारत को आजादी मिलने तक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट भारत की आजादी के पक्षधर रहे। आजादी के बाद के कुछेक दशक तक दोनों के संबंध सौहार्द पूर्ण बने रहे। लेन–देन पर आधारित दोनों देशों की नीति के तहत जहाँ अमेरिका ने पब्लिक ला 480 के जरिए भारत को जरूरी खाद्य सहायता उपलब्ध कराई, वही शांति प्रिय देश भारत ने 1950 के दशक में शांति के लिए अमेरिकी परमाणु पहल का समर्थन किया। यह अलग बात है कि बाद में यही सहयोग दोनों के बीच स्थायी दरार का कारण बना। भारत द्वारा पोखरण द्वितीय, मई 1998 ने भारत को विश्व में एक परमाणु शक्ति के रूप में पहचान बना दी बल्कि विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी भारत के प्रति नजरिया परिवर्तित हुआ। अमेरिका ने भारत को जहाँ एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में चुनौती के रूप में देखा वहीं दूसरी तरफ इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को भी समझा। इसी कारण जहाँ चुनौती के रूप में दिखाई दिया वहाँ प्रतिबन्धों का तो सहारा लिया ही बल्कि साथ–साथ सीटीबीटी पर हस्ताक्षर हेतु भी दवाब बढ़ाया, लेकिन अमेरिकी कार्यवाही पर जो भारत का दृष्टिकोण सामने आया उससे भारत अमेरिका संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हुई। जिसे विभिन्न दौर की वार्ताओं के बाद दूर किया जा सका और दोनों देशों के बीच जहाँ आपसी सूझबूझ

बढ़ी, वहीं दोनों के बीच सैनिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक एवं सामरिक तथा तकनीकी संबंध भी प्रगाढ़ हुए।

भारत अमेरिकी के बीच नजदीकी बढ़ने की शुरूआत क्लिंटन के समय से ही हो गई थी। यह प्रक्रिया जार्ज बुश के कार्यकाल में एक अहम् मुकाम पर पहुँची। इस दौरान रणनीतिक बातचीत के कई दौर सम्पन्न हुए। 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सद्भाव और सहकार के नए युग की शुरूआत मानी जाती है। इस यात्रा दौरान दोनों देशों ने दृष्टिकोण 2000 नामक दस्तावेज[2] पर हस्ताक्षर कर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए 8 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। दृष्टिकोण पत्र पर अमेरिका ने भारत के आर्थिक उदारवाद तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में हुए प्रगति की प्रशंसा करते हुए उभय पक्षीय व्यापार, निवेश सूचना पर आधारित उद्योग तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की।

जनवरी 2004 में भारत और अमेरिका ने 'रणनीतिक सहयोग में अग्रगामी छलांग' की शुरूआत की जिससे दोनों देशों को भारी प्रगति खाका खीचने का सुअवसर मिला। 2005 में दोनों देशों का सहकार और आगे बढ़ा। परिणामस्वरूप असैन्य परमाणु, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य, आर्थिक, स्वास्थ्य आपदा राहत, कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में लाए गए। मार्च, 2006 में बुश एवं मनमोहन सिंह ने युद्ध की कूटनीति से संबंधित सहयोग एवम् सांझेदारी बढ़ाने पर तथा उनके असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौते के महत्त्व पर संयुक्त वक्तव्य दिया। नवम्बर, 2009 में ओबामा के साथ व्हाइट हाऊस में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैठक कर आतकंवाद से मुकाबले के लिए सहमति पत्र तथा पांच अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक सुरक्षा के विस्तार, आतंकवाद से मुकाबला करने समझौते के अलावा शिक्षा और विकास स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक व्यापार तथा कृषि एवं हरित सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ओबामा और

प्रधानमंत्री मनमोहन के बीच शिखर के बाद दोनों देशों ने परमाणु सहयोग समझौते को संपूर्णता में लागू करने का वादा किया। परस्पर लाभ के लिए दोनों देश रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे और सामरिक वार्ता के द्वारा सैन्य स्तर पर आदान–प्रदान और रक्षा व्यापार को भी समर्थन देंगे। दोनों देश सामरिक वार्ता और साझेदारी की भावना के अन्तर्गत उच्च्य तकनीक के व्यापार को बढ़ावा देंगे। दोनों नेताओं ने एटमी हथियारों से मुक्त दुनिया की अपनी धारणा दोहराई और कहा कि परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए दोनों नेता मिलकर काम करेंगे।

नवम्बर, 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तीन दिवसीय यात्रा कई मामलों में महत्त्वपूर्ण रही। बराक ओबामा ने भारत के साथ 10 अरब डालर के नागर, विमानन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों से संबंद्ध व्यापार समझौते किए। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के छह अहम समझौते हुए। ओबामा ने अपनी यात्रा के समापन पर अमेरिका द्वारा भारत को 45 देशों के न्यूक्लियर सप्लार्यस ग्रुप में शामिल होने हेतु समर्थन, लश्कर सहित सभी आतकंवादी नेटवर्क का सफाया करने, कृषि, दोहा वार्ता, व्यापार बाधा तथा संरक्षण का खात्मा कर, पेशेवर की आवाजाही बढ़ाने, कारगर प्रभावी तथा विश्वसनीय संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु उसके यथोचित सुधार करने की जरूरत पर जोर देते हुए सामरिक साझेदारी पर बल दिया। आज भारत–अमेरिका दोनों देशों में आतंकवाद पर सहमति बनी हुई है। इसके अलावा रक्षा समझौते भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य होने के कारण भारत और अमेरिका को बाजार के रूप में खरीददार की आवश्यकता होने के कारण एवं अमेरिका का आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के कारण संबंधों में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि मनमोहन के प्रधानमंत्रीत्व काल में दोनों देशों के संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं तथा दोनों देश अनेक मुद्दों पर एक मत होने के कारण सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने पर आमादा है।[3] कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत अमेरिकी संबंधों

के बीच बदलाव का सूरज निकल रहा है। आकांक्षाओं और आशंकाओं के बादलों के बीच लुकाछिपी खेलता यह सूरज 21वीं सदी को नई दिशा व दशा दे सकने में सक्षम होगा। यह विश्वास विश्व के दो महानत्तम लोकतंत्रों का सांझा विश्वास है।

संदर्भ

1. ए. अप्पादोराए, राजन.एम.एस., इंडियाज फोरेन पॉलिसी एण्ड रिलेशंज, नई दिल्ली, 1983, पृ. 215
2. स्ट्रैटजिक एनालिसिस, मई 2000, पृ. 433
3. यादव, लक्ष्मी शंकर, प्रगाढ़ होते अमेरिका से रक्षा समझौते, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2011, पृ. 1506—08